

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1222/2014/चित्तौड़गढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट प्रथम, चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कैलाश फर्टिलाइजर
चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री वी.सी.सोगानी

अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 23.2.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 38/वैट/2013-14/चित्तौड़गढ़ में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश 18.03.2009 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपोल प्रस्तुत करने पर, उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 48 की पूर्ति नहीं करने के कारण अर्थात् बिना नोटिस जारी किये बिना ही आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को कर पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाए। अपीलीय अधिकारी के अपीलार्थीन आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण आदेश पारित समय प्रत्यर्थी व्यवहारी के विवाद अभिभाषक ने कथन किया गया है कि वक्त कर निर्धारण प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर कर निर्धारण पुनः पारित किया जावे, जिसके आधार पर ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जिससे अधिनियम अथवा नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः अपीलीय अधिकारी

के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त कर विभाग की ओर से अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि पर एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए आरोपित शास्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। उनका कथन है कि नियम नियम 48 की पालना नहीं की गई है, इसलिए आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन संयुक्त निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने द्वारा कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है, जो नियम 48 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 को उद्धृत किया जाना समीचीन है, जो इस प्रकार है :—

"65. Opportunity before imposition of penalty. – No penalty under this Act shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the dealer or the person concerned."

नियम 48 निम्न प्रकार है :—

"48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard."

अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार करारोपण से पूर्व व्यवसायी को विशिष्ट नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना विधिक रूप से आघश्यक है, जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त प्रावधानों को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2014 में उद्धरित करते हुए करारोपण एवं आरोपित शास्ति को विधिक नहीं मानते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है।

2

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2014 नो
यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की
जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनीत शर्मा)
सदस्य